(b) whether there is any proposal presently being implemented for modernisation and expansion of Visakhapatnam Port; and

(c) if so, the details of such schemes, time-frame involved and financial outlays for Visakhapatnam Port?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Reply is given in the attached Statement. *[See* Appendix CLIX, Annexure No. 21]

(b) Yes, Sir.

(c) Reply is given in the attached statement *[See* Appendix 159, Annexure No. 22]

Privatization of Shipping Industry

623. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government propose to privatise shipping industry by allowing big exporters to construct jetties and install equipment at ports;

(b) if so, to what extent privatisation of shipping industry would solve problems at ports; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): 1(a) Government welcomes the participation of Private Sector in ports.

(b) This depends upon the nature of the proposals received from the Private Sector.

(c) Till date, no firm proposal has been received.

मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में नक्सलवादी

624. श्री अजीत जोगी :
श्री राधाकिशन मालवीय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में और उससे लगे हुए महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब वहां एक समानान्तर सरकार कार्य करने लगी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस दिशा में कोई पहल की गई है; और

(ग) क्या नए सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करके इस समस्या के मूल कारणों को समाप्त किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) हाल ही के महीनों में मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में नक्सलवादियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है । लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य का विषय होने के कारण उनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की है । सरकार की यह नीति है कि देश में आतंकवादी तत्वों के साथ कड़ाई से निपटने के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास किया जाए ताकि स्थानीय लोगों की वास्तविक समस्याओं को दूर किया जा सके और उनको आतंकवादियों के प्रभाव से मुक्त रखा जा सके । तदनुसार केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से राज्य के सभी क्षेत्रों का समान विकास करने के लिए ठोस समन्वित कार्य योजनाएं तैयार करने का आग्रह करती आ रही